(b) whether it is also a fact that this year the students of Senior Secondary Examination were provided only an Urdu version question paper of economics;

(c) whether it is also a fact that most of the students could not solve the question papers as English/Hindi equivalent were not provided and the Urdu version of the terms was unfamiliar to students; and

(d) if so, what steps have been taken by Government for the next examinations ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF EDUCATION AND DEPARTMENT OF CULTURE) (KUMARI SELJA) : (a) As per information received from the Central Board of Secondary Education, bilingual question papers (English and Hindi versions) are provided to the candidates appearing in the Class X and Class XII Examinations conducted by the Board. In addition, Question Papers in Urdu version are also supplied to the candidates belonging to Delhi Administration Schools whose medium of instruction is Urdu.

(b) No, Sir.

(c) and (d) Do not arise.

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रौढ़ शिक्षा का लक्ष्य

3179. **श्री राम जेठमलानी :**
श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान कुल प्रौढ़ आबादी के 70 प्रतिशत को साक्षर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है,

(ख) यदि हां, तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने कौन सा कार्यक्रम कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है, और

(ग) इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर व्यय करने हेतु कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाने तथा प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के सम्मिलित प्रयासों से यह आशा की जाती है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक देश में साक्षरता दर लगभग 70 प्रतिशत तक बढ़ जाएगी ।

(ख) प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाने तथा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अन्तर्गत आठवीं योजना के लिए एक व्यापक कार्यक्रम आरम्भ किया गया है । प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाने के कार्यक्रम के तहत, निर्धारित लक्ष्य निम्नवत् हैं :—

पहुंच :

1. सभी बच्चों, जिनमें लड़कियां तथा अनु. जाति/अनु. जनजाति के व्यक्ति भी शामिल हैं, का सर्वव्यापक नामांकन;

2. एक किलोमीटर की पैदल दूरी के भीतर वाले क्षेत्र में सभी बच्चों के लिए प्राथमिक स्कूलों का प्रावधान तथा पढ़ाई बीच में छोड़ जाने वाले, स्कूल न जा सकने वाले कामकाजी बच्चों तथा लड़कियों के लिए अनौपचारिक शिक्षा की सुविधा;

3. अपर प्राथमिक स्कूलों से प्राथमिक स्कूलों के मौजूदा अनुपात 1 :4 को 1 : 2 करके उसमें सुधार करना जो कि अपर प्राथमिक स्तर पर लड़कियों की सहभागिता में वृद्धि करने के व्यापक अवसरों के लिए एक पूर्व-शर्त होगी ।

सहभागिता :

4. पहली से पांचवी तथा पहली से आठवीं कक्षाओं के बीच, पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले छात्रों की दर मौजूदा 40% तथा 60% से कम करके क्रमश: 20% तथा 40% करना ।

उपलब्धि

5. प्राथमिक स्तर पर वर्तमान: सभी बच्चों द्वारा शिक्षा के न्यूनतम स्तर प्राप्त करना तथा इस प्रक्रिया को अपर प्राथमिक स्तर पर भी प्रारम्भ करना ।

जहां तक राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का संबंध है, योजनावधि के दौरान, पूर्ण साक्षरता अभियानों के तहत, 345 जिलों को शामिल करने का प्रस्ताव है ।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, प्रारम्भिक शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के लिए क्रमश: 2800 करोड़ तथा 1400 करोड़ रुपए की कुल राशि केन्द्रीय सैक्टर में आबंटित की गई ।

Deemed and Statutory Urdu Universities

3180 DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICHKAR : Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) the number and names of the Urdu Universities (Deemed and Statutory) in the country and the number of students enrolled in each of them;

(b) the total expenditure incurred by Government on them during the last three years; and

(c) whether Government propose to establish any new Urdu University ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF EDUCATION AND DEPARTMENT OF CULTURE) (KUMARI SELJA) : (a) According to the information furnished by the University Grants Commission, there is no Urdu University in the country at present.

(b) Does not arise.

(c) Government has constituted a Committee under the Chairmanship of Shri Aziz Qureshi, ex-M.P., to consider in detail all aspects of the establishment of a Urdu University and make suitable recommendations to the Government in this regard.

Kendriya Vidyalaya Sangathan Employees under CAT

3181. SHRI MISA R. GANESAN :

SHRI MOHD. KHALEELUR RAHMAN :

SHRI SARADA MOHANTY :

SHRI N. GIRI PRASAD :

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether AIKVTA has been demanding that Kendriya Vidyalaya Sangathan employees be brought under the jurisdiction of Central Administrative Tribunal; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF EDUCATION AND DEPARTMENT OF CULTURE) (KUMARI SELJA) : (a) and (b) Yes, Sir. Kendriya Vidyalaya Sangathan, being a Society under Societies' Registration Act, does not automatically come under the Jurisdiction of Central Administrative Tribunal, Section 14(2) of the Central Administrative Tribunal Act-1985, empowers the Central Government to issue notification for bringing Corporations/ Societies owned or controlled by the Government of India within the jurisdiction of Central Administrative Tribunal in regard to service matters of the employees of such bodies. No such notification for Kendriya Vidyalaya Sangathan, could be issued as the Central Administrative Tribunal is not enquipped at present to bear any extra work load.

प्रशिक्षार्थियों का प्रौढ़ शिक्षा में भाग न लेना

3182. **श्री गोपाल सिंह जी. सोलंकी :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि बहुत से प्रशिक्षार्थी सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाओं और शुल्क-अदायगी के भय से प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों में भाग नहीं लेते हैं;